PRGI. No.: MHMUL/25/A2419

प्यूपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 ‣ Issue : 21 ‣ Mumbai ‣ Friday, 26 June to 2 July 2026 ‣ Weekly ‣ Pages : 8 ‣ Price : 3 Rs.

पीएम मोदी से मिले ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

वैश्विक चुनौतियों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) बैठक के दो दिवसीय कार्यक्रम के बाद ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें इन सभी सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा, "बदलते वैश्विक माहौल में ब्रिक्स की भूमिका बहुत अहम है। यह सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और नई तकनीकों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। (शेष पेज-5 पर देखें)

रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक

अधिकारी बोले-सीमा क्षेत्रों में पर्याप्त सैनिक तैनात

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सांसद राधा मोहन सिंह ने की और इस बैठक का एजेंडा 'देश की रक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की भूमिका' था। बैठक में सीडीएस जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि के नेतृत्व में सेना के टॉप अधिकारियों ने देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। समिति को बॉर्डर पर सैन्य तैनाती और रणनीतिक तौर पर अहम क्षेत्रों में सेना की मौजूदगी के बारे में ब्रीफ किया गया। सूत्रों के मुताबिक, सेना के अधिकारियों ने समिति को बताया कि सीमा क्षेत्रों और रणनीतिक महत्व वाले जगहों पर पर्याप्त संख्या में सैनिक तैनात किए गए हैं, ताकि देश विरोधी तत्वों की किसी भी नापाक साजिश को नाकाम किया जा सके।

संक्षिप्त खबरें

तृणमूल को फिर से कैडर आधारित बनाने की तैयारी में ममता बनर्जी

कोलकाता: बंगाल विधानसभा चुनाव में हार और सांसदों-विधायकों की बड़ी बगावत के बाद तृणमूल कांग्रेस ने संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अब अपने पुराने कैडर आधारित ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है।

इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद बढ़ाएंगे तथा पार्टी के संगठनात्मक कामकाज में राजनीतिक सलाहकार संस्था आइपैक की भूमिका सीमित की जाएगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत उसका संगठन होता है। बाहरी एजेंसियां केवल सीमित सहयोग दे सकती हैं, लेकिन संगठन का संचालन पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही होना चाहिए। इसी सोच के तहत आइपैक पर निर्भरता कम करने का निर्णय लिया गया है।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश की नई टीम घोषित की

कई नए चेहरों को मिली जिम्मेदारी

लखनऊ: यूपी भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले नई टीम का एलान कर दिया है। भाजपा की नई टीम में ओबीसी को तरजीह दी गई है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को भाजपा उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा पूजा पाल और सुरेश राणा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री शामिल हैं। इसी तरह पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। सरोज कुशवाह को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देवेंद्र सिंह किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। अशोक रावत अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रकाश पाल पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दिनेश प्रताप सिंह मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। रोहित मिश्रा भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। (शेष पेज-2 पर देखें)

इन नेताओं को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया

रामप्रताप सिंह चौहान	महामंत्री
गीता शाक्य	महामंत्री
अभिजात मिश्रा	महामंत्री
उपेंद्र रावत	महामंत्री
संजय राय	महामंत्री
शंकर लोधी	महामंत्री
दिलीप पटेल	महामंत्री
राजेश चौधरी	महामंत्री

वेनेजुएला में भूकंप से भीषण तबाही

मृतकों की संख्या 164 हुई, 1 हजार से ज्यादा घायल

काराकस। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने जनहानि को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या 32 से बढ़कर 164 हो गई है, वहीं घायलों की तादाद भी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। पहले जहां 700 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही थी, वहीं अब ये 971 तक पहुंच गई है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद वेनेजुएला में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 लोग घायल हुए हैं। नए आंकड़े पहले बताए गए 32 मृतकों और 700 घायलों की संख्या से काफी ज्यादा हैं। अधिकारियों का कहना है कि राहत-बचाव कार्य जारी है। इससे लग रहा है कि संख्या और बढ़ सकती है। रोड्रिगेज ने कहा कि अधिकारी देश के दूसरे हिस्सों से बचाव टीमों को सबसे ज्यादा प्रभावित ला गुएरा इलाके में भेज रहे हैं, जो राजधानी काराकस के उत्तर में है। उन्होंने कहा, "वहां दर्जनों इमारतें गिर गई हैं... और हम अभी जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रहे हैं।" रोड्रिगेज ने कहा कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जुटाया जा रहा है। इस बीच, दुनिया के तमाम देशों ने वेनेजुएला को हरसंभव सहायता पहुंचाने का भरोसा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पोस्ट के जरिए संवेदना व्यक्त करते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। रोड्रिगेज ने जवाब में पीएम मोदी का आभार जताया। इस बीच, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने चेतावनी दी है कि इस आपदा में मृतकों की संख्या काफी बढ़ सकती है। (शेष पेज-2 पर देखें)

भारतीय तटरक्षक बल के लिए बन रहा है चौथा नेक्स्ट जेनरेशन ओपीवी

नई दिल्ली: भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक और 'नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल' का निर्माण शुरू किया गया है। यह भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए बनाए जा रहे छह नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल में से चौथा पोत है। इस से भारत की समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। गुरुवार को इस अत्याधुनिक पोत की कील-लेइंग यानी जहाज की आधारशिला स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। यह पोत मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और आधुनिक प्रणालियों के साथ निर्मित किया जा रहा है। समारोह में भारतीय तटरक्षक बल और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स

लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह परियोजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ-साथ देश की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली मानी जा रही है। गौरतलब है कि समुद्री जहाज निर्माण की प्रक्रिया में कील-लेइंग समारोह को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। यह वह चरण होता है जब जहाज के मुख्य ढांचे का निर्माण औपचारिक रूप से शुरू होता है। किसी भी युद्धपोत या गश्ती पोत के निर्माण कार्यक्रम में यह एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक अवसर होता है। निर्माणाधीन नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल आधुनिक मशीनरी, उन्नत सेंसर, अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और नवीनतम समुद्री निगरानी उपकरणों से लैस होंगे। इन पोतों को लंबी दूरी की गश्त, तटीय निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान, समुद्री कानून प्रवर्तन तथा विशेष सुरक्षा अभियानों के लिए तैयार किया जा रहा है। (शेष पेज-2 पर देखें)

संपादकीय

सूखे की आशंका

यह अच्छा हुआ कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो प्रभाव के चलते मानसून में कमी को देखते हुए सूखे की आशंका से निपटने के लिए फिर से बैठक की। इसके पहले उन्होंने एक बैठक इस माह के प्रारंभ में भी की थी। गत दिवस की बैठक में उन 315 जिलों की पहचान की गई, जो सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इन जिलों में भी 111 ऐसे हैं, जहां सूखे का असर कहीं अधिक हो सकता है। निःसंदेह भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बारिश में कमी एक गंभीर चुनौती है। सूखे की आशंका केवल किसानों की ही समस्या नहीं बढ़ाएगी, बल्कि कमजोर फसल के नतीजे में अनाज के महंगे होने से आम आदमी भी प्रभावित हो सकता है। फसल उत्पादन में कमी को देखते हुए सरकार को खाद्य सुरक्षा के प्रति सचेत होना होगा। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि कमजोर मानसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। निःसंदेह बारिश में कमी के चलते चुनौती केवल सिंचाई के जल के अभाव के रूप में ही पैदा नहीं होगी, बल्कि देश के कुछ इलाकों में पेयजल संकट भी बढ़ सकता है। वैसे भी गर्मियों में देश के कई हिस्से इस संकट से दो-चार होते ही हैं। स्पष्ट है कि कृषि मंत्रालय के साथ जलशक्ति मंत्रालय को भी सक्रिय होना होगा। अब जब सूखे की आशंका गहराती जा रही है, तब फिर उसके असर से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जानी चाहिए। इस तैयारी के अनुकूल परिणाम तभी मिलेंगे, जब राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी। इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इस बार बारिश कम होने जा रही है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है कि किसानों को कम पानी वाली फसलें उगाने के लिए आवश्यक सलाह और सहायता देने में देर न की जाए। इसी तरह यह भी देखा जाए कि जलाशयों के जल का समुचित उपयोग हो। यह सही समय है कि जल संरक्षण के साथ वर्षा का पानी बचाने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। पानी की बबार्दी को रोकने के भी यथासंभव उपाय करने होंगे और इसमें हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। चूंकि अपने देश की समस्या यह है कि कृषि का एक बड़ा हिस्सा बारिश के जल पर निर्भर है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वर्षा जल संचयन संबंधी योजनाओं की समीक्षा हो। इसकी कोशिश हर स्तर पर होनी चाहिए कि बारिश के जल का अधिकाधिक संचयन हो सके। चूंकि अल नीनो प्रभाव के अतिरिक्त जलवायु में लगातार परिवर्तन एक हकीकत है, इसलिए उससे उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों पर सतत ध्यान देने की रणनीति समय की मांग है। बारिश होते ही सूखे से निपटने के दीर्घकालिक उपायों की अनदेखी ठीक नहीं।

छात्रों के हित में है त्रिभाषा फामूर्ला

भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम भर नहीं होती, इसका एक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र भी होता है। खासतौर से जब भाषा का परिप्रेक्ष्य शिक्षा के संदर्भ में हो तो भाषा अपने समाजशास्त्र और आर्थिकी से आगे बढ़कर राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया से भी जुड़ जाती है। पिछले दिनों देश में सीबीएसई के स्कूलों में त्रिभाषा फामूर्ले को लागू करने की योजना की घोषणा को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। यह अलग बात है कि इस मुद्दे पर पूरे देश में एक विवाद खड़ा कर दिया गया है। यह संतोषजनक है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्णय पर रोक नहीं लगाई। भारत के प्रमुख स्कूली शिक्षा बोर्ड ह्यकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डह्ण (सीबीएसई) ने हाल में निर्णय लिया कि अकादमिक सत्र 2026-2027 से छठी और नवीं कक्षा से त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा है। इसके अनुसार स्कूली स्तर पर तीन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी। पहले भी एनईपी 1968 और एनईपी 1986 आदि में थोड़े से भिन्न रूप में त्रिभाषा फामूर्ला अपनाया गया था। एकाध को छोड़कर सभी राज्यों ने त्रिभाषा सूत्र को लागू किया, लेकिन दुर्भाग्य से सीबीएसई ने त्रिभाषा फामूर्ले को आंशिक रूप से ही स्वीकारा था। सीबीएसई स्कूलों में छठी से आठवीं तक त्रिभाषा सूत्र लागू तो था, लेकिन तीसरी भाषा के तौर पर विदेशी भाषाओं की भी छूट थी, फिर नवीं और दसवीं में तो सीबीएसई ने सिर्फ द्विभाषा नीति ही अपनाई थी। उसमें भी छूट यहां तक कि स्कूल चाहें तो दोनों ही भाषाएं कोई गैर-भारतीय भाषा हो सकती थीं। इसका दुष्परिणाम हुआ कि महंगे पब्लिक स्कूलों में भारतीय भाषाओं को उपेक्षित किया जाने लगा। सीबीएसई की इन नीतियों से कई विसंगतियां पैदा हो गई थीं। सीबीएसई एवं

राज्य बोर्डों के विद्यार्थियों में भाषा शिक्षण में असंतुलन की स्थिति बन गई थी। वर्तमान योजना का उद्देश्य देशभर में स्कूली शिक्षा में समानता एवं भाषाई एकरूपता स्थापित करना है। दूसरे, नवीं और दसवीं में जब बच्चों का व्यक्तित्व आकार लेना शुरू करता है, उस समय केवल विदेशी भाषाओं तक सीमित रह जाना, बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति से दूर करना है। भाषा सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों का भी संचार करती है। आज बच्चों में त्याग, सेवा, सहिष्णुता, सामूहिकता, परिवार-भाव, बड़ों के प्रति आदर जैसे भारतीय मूल्यों का लोप हो रहा है। एनईपी 2020 का त्रिभाषा सूत्र बच्चों में क्षीण हो रहे इन भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करेगा। सीबीएसई के बच्चों को भी बहुभाषिकता की शक्ति का लाभ मिलेगा। साइको-लिंग्विस्टिक रिसर्च बताती हैं कि बच्चों में अनेक भाषाएं सीखने की सहज और असीम क्षमता होती है। एक से अधिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान बच्चों में भारतीय भौगोलिक-सांस्कृतिक समझ को समृद्ध करेगा। इससे राष्ट्रीय एकता के भाव को मजबूती मिलेगी और विभाजनकारी भाषाई राजनीति कमजोर होगी। भाषा का एक अर्थशास्त्र भी होता है। भारतीय भाषाओं के अध्ययन-अध्यापन से इससे जुड़े प्रकाशन उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लोगों को देशभर में घुलने-मिलने, रोजगार, व्यापार, शिक्षा और पर्यटन में आसानी होगी। विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही सूचनाएं तथ्यहीन एवं भ्रामक हैं। विरोध का एक कारण अंग्रेजी-शिक्षित आभिजात्य वर्ग की औपनिवेशिक दौर की 'मैकाले मानसिकता' भी है। एक अध्ययन के अनुसार तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषाओं की पढ़ाई केवल एक प्रतिशत शहरी विद्यार्थी ही कर रहे हैं। भारतीय भाषाओं के अध्ययन की अनिवार्यता का विरोध इन्हीं के आभिजात्य अभिभावकों द्वारा किया जा रहा है। नए दिशानिदेर्शों के विरोध में ये लोग भाषा शिक्षकों की कमी, पाठ्यपुस्तकों का अभाव, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ और तनाव, पहले से विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर रहे छात्रों की असुविधा आदि तर्क दे रहे हैं। ध्यान रहे कि सीबीएसई/एनसीईआरटी द्वारा कक्षा छह के लिए सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें लगभग तैयार हैं। नवीं कक्षा में त्रिभाषा नीति 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी। इसके लिए 19 अनुसूचित भाषाओं की पाठ्यपुस्तकें शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी। अन्य भारतीय भाषाओं के लिए इस वर्ष एनसीईआरटी की पुस्तकों का उपयोग कर सकेंगे। शिक्षकों के लिए नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर आनलाइन पद्धति में अन्य स्कूलों से सहयोग कर शिक्षण कार्य असंभव नहीं। केवल एक और भारतीय भाषा की पढ़ाई को अतिरिक्त बोझ बताना, सही समझ का अभाव है। विभिन्न राज्यों में पहले से ही तीन भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। पहले से विदेशी भाषाएं पढ़ रहे छात्रों की सुविधा के लिए वर्तमान में तीसरी भाषा का पाठ्यक्रम हल्का रखा जाएगा। तीसरी भाषा के लिए यह छूट भी है कि दसवीं में इसकी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। यही नहीं, कोई छात्र अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरी विदेशी भाषा भी सीखना चाहे तो इसका भी अवसर प्राप्त होगा। बड़े सुधारों में प्रारंभ में कुछ चुनौतियां आना स्वाभाविक हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि त्रिभाषा नीति को सही रूप से लागू करना देश और बच्चों, दोनों के हित में है।

चुनौतियों के साथ अवसरों का भी दौर

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। एक ओर खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर थोक महंगाई में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। हाल के भू-राजनीतिक तनावों में कमी के बाद रुपया फिर मजबूती की ओर बढ़ा है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है और भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह तस्वीर आश्वस्त करने वाली है, पर इसके भीतर कुछ ऐसे संकेत भी छिपे हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण संकेत थोक और खुदरा महंगाई के बीच बढ़ता अंतर है। हाल में थोक महंगाई तेजी से बढ़ी है, जबकि खुदरा महंगाई अपेक्षाकृत नियंत्रित रही है। यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहती। उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि का बोझ अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचता ही है। इसलिए आज जो दबाव उद्योगों और उत्पादकों पर दिखाई दे रहा है, उसका असर आने वाले समय में आम उपभोक्ता की जेब पर भी पड़ सकता है। थोक महंगाई मुख्यतः उन लागतों को दर्शाती है, जिनका सामना उत्पादकों को करना पड़ता है। जब ऊर्जा, परिवहन, आयातित कच्चे माल और विनिर्माण की

लागत बढ़ती है, तब कंपनियां शुरूआत में अपने मुनाफे में कटौती करके कुछ बोझ स्वयं वहन करती हैं, पर यदि लागत का दबाव बना रहता है तो अंततः कीमतों में वृद्धि करनी पड़ती है। थोक महंगाई में हाल की तेजी को केवल एक अस्थायी घटना मानना उचित नहीं होगा। इस बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण ऊर्जा लागत है। वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईंधन और बिजली की ऊंची कीमतों ने उत्पादन लागत को बढ़ाया है। सकारात्मक पक्ष यह है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से वैश्विक तेल कीमतों में नरमी आई है। भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए यह राहत के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर भी है। अक्सर कम तेल कीमतों को अतिरिक्त खर्च करने का अवसर समझ लिया जाता है, पर यह दृष्टिकोण दूरदर्शी नहीं होगा। बाजारों के उतार-चढ़ाव स्थायी नहीं होते। समझदारी इसी में है कि अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने में किया जाए। सबसे पहले घटी तेल कीमतों से होने वाले लाभ का उपयोग बाहरी क्षेत्र की मजबूती के लिए किया जाना चाहिए। जब तेल आयात बिल घटता है तो चालू खाते का संतुलन बेहतर होता है। इस अवसर का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को और मजबूत करने में किया जा सकता है। मजबूत भंडार केवल आर्थिक शक्ति का प्रतीक नहीं होते, बल्कि भविष्य के वैश्विक झटकों के खिलाफ सुरक्षा कवच भी प्रदान करते हैं। दूसरा, यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का उपयुक्त समय है। पिछले एक दशक में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं।

सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रत्येक नई प्रगति भारत की आयातित ऊर्जा पर निर्भरता को कम करेगी। यह पर्यावरण संरक्षण संग आर्थिक सुरक्षा का भी प्रश्न है। तीसरा, कम ऊर्जा लागत भारत के निर्यात क्षेत्र के लिए भी अवसर लेकर आई है। ढुलाई खर्च घटने से भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। लक्ष्य निर्यात बढ़ाने के साथ वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी को स्थायी रूप से मजबूत करना होना चाहिए।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश की नई टीम घोषित की...

इन नेताओं को मिली प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

सुरेश राणा-उपाध्यक्ष, सत्यपाल सैनी-उपाध्यक्ष, ब्रज बहादुर-उपाध्यक्ष, डॉ धर्मेंद्र सिंह-उपाध्यक्ष, मोहित बेनीवाल-उपाध्यक्ष, देवेश कोरी-उपाध्यक्ष, प्रियंका रावत-उपाध्यक्ष, दुर्विजय शाक्य-उपाध्यक्ष, रमेश सिंह-उपाध्यक्ष, नीरज सिंह-उपाध्यक्ष, अर्चना मिश्रा-उपाध्यक्ष, पूजा पाल-उपाध्यक्ष, शंकर गिरी-उपाध्यक्ष, कामेश्वर सिंह-उपाध्यक्ष, कृतिका अग्रवाल-उपाध्यक्ष, सुरेश मौर्य-उपाध्यक्ष, राजेश यादव-उपाध्यक्ष, कृष्ण बिहारी राय-उपाध्यक्ष, आलोक गुप्ता-उपाध्यक्ष

वेनेजुएला में भूकंप से भीषण तबाही...

इसके 10 हजार से एक लाख तक भी पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों में काराकस की सड़कों पर कई घर भरभरा कर गिरे देखे जा सकते हैं। बुधवार को एक के बाद एक दो भूकंप के झटकों से देश दहल गया था। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर पहले की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 मापी गई। वेनेजुएला में एक सदी से भी ज्यादा समय में आए ये सबसे शक्तिशाली भूकंप के झटके थे।

भारतीय तटरक्षक बल के लिए बन रहा है चौथा नेक्स्ट जेनरेशन ओपीवी...

इनकी तैनाती से भारतीय तटरक्षक बल की समुद्र में निगरानी क्षमता और प्रतिक्रिया समय में उल्लेखनीय सुधार होगा। भारतीय तटरक्षक बल और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के बीच 20 दिसंबर 2023 को छह नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के निर्माण का अनुबंध संपन्न हुआ था। इस परियोजना का उद्देश्य तटरक्षक बल के बेड़े का आधुनिकीकरण करना और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे और अधिक सक्षम बनाना है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक गतिविधियों और समुद्री चुनौतियों को देखते हुए भारतीय तटरक्षक बल लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। ऐसे में नए एनजीओपीवी पोत तस्करी, अवैध मछली पकड़ने, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, आपदा राहत और खोज-बचाव अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं, इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका स्वदेशी स्वरूप है। जहाज का डिजाइन, विकास और निर्माण भारत में ही किया जा रहा है, जिससे देश के रक्षा-उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र, जहाज निर्माण क्षेत्र और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

प्यूपिल्स टाइम्स

बेस्ट कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली

मुंबई : डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक के साथ बातचीत के बाद अलग-अलग फेज में बस सर्विस फिर से शुरू हो गई हैं। BEST की बसें फिर से सड़कों पर दौड़ती दिख रही हैं। सुबह से शुरू हुई बारिश के बाद बस सर्विस फिर से शुरू होने से मुंबईकरों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि, जानकारी सामने आई है कि अभी सभी रूट पर सर्विस पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, और सुबह के सेशन में कुछ रूट पर बस सर्विस शुरू नहीं हो पाई। शुक्रवार से चल रही इस हड़ताल का मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बड़ा असर पड़ा।

सह्याद्री गेस्ट हाउस में राज्य सरकार और हड़ताली कर्मचारी यूनियन के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर पॉजिटिव फैसला होने के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया। बातचीत के दौरान, सरकार ने कर्मचारियों की कुछ जरूरी मांगें मान लीं। इसके मुताबिक, परमानेंट कर्मचारियों की महीने की सैलरी में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा, सरकार मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के बजट से पेंडिंग ग्रेच्युटी अमाउंट देने पर सहमत हो गई है। कर्मचारियों के लिए कैंटीन, टॉयलेट और दूसरी बेसिक सुविधाओं में सुधार का भी वादा किया गया।

10वीं-12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के दौरान स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग सेवा

मुंबईः महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा जून-जुलाई 2026 में आयोजित सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (क्लास) और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (क्लास II) सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के दौरान स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और गाइडेंस देने के लिए अलग-अलग लेवल पर काउंसलिंग सर्विस उपलब्ध कराई गई हैं। स्टेट बोर्ड के अनुसार, 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 30 जून, 2026 तक आयोजित की गई है, जबकि 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 8 जुलाई, 2026 तक पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोंकण जोनल बोर्ड के जरिए आयोजित की गई है। एग्जाम के समय स्टूडेंट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा देने के लिए स्टेट बोर्ड लेवल पर काउंसलर नियुक्त किए गए हैं और उनसे इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है: 7208429381, 9404783996 और 9960644411। इस साल से, बोर्ड मुक्तांगन मित्र संस्था के जरिए क्लास 10वीं और 12वीं के एग्जाम से जुड़े स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स को काउंसलिंग सर्विस दे रहा है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 9112709112 चालू है। टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर 14416 और मनोदर्शन हेल्पलाइन नंबर 8448440632 पर भी काउंसलिंग सर्विस उपलब्ध हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के जरिए भी 315 काउंसलर की सर्विस दी गई हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर और पते महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। स्टेट बोर्ड सेक्रेटरी डॉ. दीपक माली ने सप्लीमेंट्री एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स से अपील की है कि वे बिना किसी स्ट्रेस या कन्फ्यूजन के उपलब्ध काउंसलिंग सर्विस का फायदा उठाएं।

महाराष्ट्र : राज्य में किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी 36,585 करोड़ रुपये की लोन माफी

मुंबईः किसानों को दी गई लोन माफी राज्य सरकार के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि किसानों को राहत देने का एक तरीका है। भले ही आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए लोन माफ करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत 36,585 करोड़ रुपये की लोन माफी दी जाएगी और इससे करीब 56 लाख किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि यह राज्य में अब तक की सबसे बड़ी लोन माफी है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला किसानों को कानूनी किसान का दर्जा देने वाला बिल विधानसभा के मानसून सेशन में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य विधानसभा के मानसून सेशन से एक दिन पहले सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा अजीत पवार, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले, वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर गिरीश महाजन, कोऑपरेशन मिनिस्टर बाबासाहेब पाटिल और दूसरे लोग मौजूद थे।

लोन माफी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं

यह कहते हुए कि राज्य सरकार विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान आम लोगों के मुद्दों पर पॉजिटिव तरीके से चर्चा करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कमिटेड है, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हालांकि लोन माफी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मुश्किल में फंसे किसानों को राहत देने के लिए यह जरूरी है। सरकार लोन माफी को किसानों को फिर से खड़ा होने और उन्हें नए लोन मिलने का रास्ता बनाने में मदद करने के लिए एक जरूरी टूल के तौर पर देखती है। सरकार ने लोन माफी को लेकर एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई थी और उसे शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म उपायों के साथ-साथ बैंकिंग सिस्टम पर पड़ने वाले असर की स्टडी करने की ज़िम्मेदारी दी थी। कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं। यह पक्का करने के लिए कि लोन माफी को लागू करते समय किसानों के साथ कोई नाइंसाफी न हो, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कुछ मंत्रियों की एक सब-कमेटी बनाई गई है और उसे जरूरी बदलाव करने का अधिकार दिया गया है, ऐसा फडणवीस ने यह भी कहा।

बीएमसी ने जुलाई में अतिरिक्त 10% और पानी कटौती की चेतावनी दी

मुंबईः बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (इटउ) जुलाई के पहले हफ़्ते में 10% और पानी की कटौती करने पर विचार कर रही है, अगर जून के आखिर में होने वाली बारिश के बाद भी रिजर्वॉयर का लेवल नहीं सुधरा। मुंबई में पानी की सप्लाई को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं क्योंकि शहर को पीने का पानी देने वाले सात रिजर्वॉयर में कुल स्टोरेज कुल कैपेसिटी के 10% से कम हो गया है।सिविक बॉडी ने पहले ही 10% पानी की कटौती लागू कर दी है और डिमांड को मैनेज करने के लिए सरकारी सोर्स से एक्स्ट्रा रिजर्व पानी ले रही है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर के मुताबिक, मौजूदा पानी का स्टॉक, रिजर्व सप्लाई के साथ, लगभग 20 अगस्त तक शहर की जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद है।इस मुद्दे पर एक मीटिंग के दौरान चर्चा हुई, जहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टियों के कॉर्पोरेटर्स ने

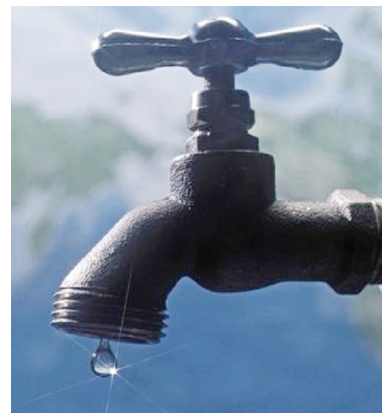

सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारियों और इमरजेंसी प्लान के बारे में डिटेल्स माँगी। बांगर ने स्थिति की गंभीरता को माना, और कहा कि एल नीनो से जुड़े मौसम के पैटर्न से साल के आखिर में तापमान बढ़ सकता है, जिससे रिजर्वॉयर से इवैपोरेशन लॉस बढ़ सकता है।

बीएमसी ने बिना इजाजत के चल रहे 53 झुग्गी-झोपड़ी स्कूलों पर केस दर्ज किया

मुंबईः मुंबई में बिना इजाजत वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने झुग्गी-झोपड़ियों में मौजूद 53 स्कूलों पर सरकारी मंजूरी के बिना चलने का आरोप लगाया है। यह कार्रवाई बार-बार दी गई चेतावनी और बंद करने के नोटिस के बाद की गई, जिन्हें कथित तौर पर स्कूलों ने नजरअंदाज कर दिया था।

164 इंस्टीट्यूशन की बड़ी लिस्ट का हिस्सा

ये स्कूल उन 164 इंस्टीट्यूशन की बड़ी लिस्ट का हिस्सा थे जिन्हें पहले सिविक अधिकारियों ने गैर-कानूनी घोषित किया था। इन स्कूलों को फरवरी में बंद करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि ये मौजूदा एजुकेशन नियमों के तहत जरूरी परमिशन के बिना चल रहे थे। जब नियमों का पालन नहीं किया गया, तो उनमें से कई के खिलाफ FIR दर्ज की गई। प्रभावित स्कूलों में से ज्यादातर मानखुर्द और गोवंडी से थे, जबकि दूसरे मालवानी में थे। सिविक अधिकारियों ने संकेत दिया कि अगर वे आधिकारिक निदेशों के बावजूद चलते रहे तो और इंस्टीट्यूशन पर भी ऐसी ही कार्रवाई की जा सकती है। इस कदम ने शहर भर में इनफॉर्मल बस्तियों में चल रही एजुकेशनल सुविधाओं को रेगुलेट करने की लंबे समय से चली आ रही चुनौती को सामने लाया है।

मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन

इस कार्रवाई के बाद स्टूडेंट्स की भलाई एक बड़ी चिंता बनकर उभरी है। अधिकारियों ने कहा है कि जिन स्कूलों पर असर पड़ा है, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई से मना नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। उम्मीद है कि एडमिशन उम्र की योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे, और स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बिना इजाजत वाले इंस्टीट्यूशन से जारी किए गए डॉक्यूमेंट कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इस बदलाव को आसान बनाने के लिए, इटउ के स्कूलों को एडमिशन में एक्टिव रूप से मदद करने का निर्देश दिया गया है। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू मीडियम के सिविक स्कूलों को एनरोलमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेने का निर्देश दिया गया है। शिवाजीनगर में एक नई बनी स्कूल बिल्डिंग से और कैपेसिटी भी मिलने की उम्मीद है, जो जल्द ही चालू होने वाली है।

हालांकि, प्रभावित स्कूलों के प्रतिनिधियों ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। यह तर्क दिया गया है कि इनमें से कई इंस्टीट्यूशन आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनकी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई तक पहुंच कम हो सकती है। स्कूल चलाने वालों का कहना है कि अक्सर मंजूरी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वे कम से कम क्लासरूम साइज और खास खेल के मैदान जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, जिन्हें वे घनी आबादी वाली झुग्गी-झोपड़ियों में प्रैक्टिकल नहीं मानते।

स्लम प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने भी FIR दर्ज होने पर नाखुशी जताई है। दावा किया गया है कि रेगुलराइजेशन के लिए बार-बार कोशिशें की गई थीं और सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत से पहले पॉलिसी में बदलाव या रेगुलेटरी छूट की उम्मीद जगी थी। कुछ स्कूल प्रतिनिधि अब सिविक बॉडी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। इस बीच, शिक्षा के हिमायतियों ने अधिकारियों से यह पक्का करने की अपील की है कि स्टूडेंट्स इस विवाद के नतीजों से सुरक्षित रहें। इस बात की चिंता जताई गई है कि कई माता-पिता को उन स्कूलों के कानूनी स्टेटस के बारे में पता नहीं होगा जिनमें उनके बच्चों का एडमिशन हुआ था। जैसे-जैसे विवाद जारी रहेगा, उम्मीद है कि मुंबई भर में हजारों कमजोर स्टूडेंट्स की पढ़ाई की जरूरतों के साथ रेगुलेटरी एनफोर्समेंट को बैलेंस करने पर ध्यान रहेगा।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव

महायुति गठबंधन ने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की

मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 17 में से 16 सीटें अपने नाम कर ली हैं। हालांकि, नासिक में सत्तारूढ़ गठबंधन की इस जीत में खलल पड़ा, जहां निर्दलीय प्रत्याशी ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट को हरा दिया। द्विवार्षिक चुनावों का सोमवार को मतगणना के साथ समापन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की शानदार जीत का नेतृत्व किया जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) को स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा।

18 जून को 11 सीटों पर मतदान से पहले ही महायुति गठबंधन ने छह सीटें निर्विरोध जीत ली थीं। सोमवार को अंतिम घोषणा के साथ ही सत्ताधारी गठबंधन ने चुनावों में पूर्ण दबदबा कायम कर लिया, जिसमें भाजपा (11 सीटें), शिवसेना (शिंदे) (3 सीटें), एनसीपी (अजित पवार) (2 सीटें) और निर्दलीय (1 सीट) शामिल हैं। चुनाव 18 जून को 11 सीटों पर मतदान से पहले ही महायुति गठबंधन ने छह सीटें निर्विरोध जीत ली थीं। सोमवार को अंतिम घोषणा के साथ ही सत्ताधारी गठबंधन ने चुनावों में पूर्ण दबदबा कायम कर लिया, जिसमें भाजपा (11 सीटें), शिवसेना (शिंदे) (3 सीटें), एनसीपी (अजित पवार) (2 सीटें) और निर्दलीय (1 सीट) शामिल हैं। भंडारा-गोंदिया में भाजपा के अविनाश ब्रम्हणकर ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नरेश ईश्वरकर को 148 वोटों के अंतर से हरा दिया। ईश्वरकर के 152 के मुकाबले अविनाश ब्रम्हणकर को 304 वोट मिले। छत्रपति संभाजीनगर-जालना में भाजपा के सुहास शिरसाट ने शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार गणेश लोखंडे को हराया और लोखंडे के 134 वोटों के मुकाबले सुहास शिरसाट ने 454 वोट हासिल किए। नांदेड़ में महायुति पार्टी के अमरनाथ राजुरकर ने 339 वोट हासिल करके शानदार जीत दर्ज की। एमवीए उम्मीदवार कृष्णा पाटिल अष्टिकर को केवल 84 वोट मिले जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के उम्मीदवार प्रशांत इंगोले मात्र 5 वोटों से पिछड़ गए। धराशिव-लातूर-बीड़ में भाजपा के बसवराज पाटिल ने 845 वोट से जीतकर विधानसभा में आसानी से प्रवेश कर लिया। सांगली-सतारा में भाजपा के धैर्यशील कदम ने जीत के लिए आवश्यक 443 वोटों का कोटा पार कर लिया। कदम को 591 प्रथम वरीयता वोट मिले और उन्होंने एनसीपी के अभय सिंह जगताप (295 वोट) को हरा दिया। जलगांव में भाजपा के नंदकिशोर महाजन ने 577 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। इस हार के बाद पिछड़ रहे एमवीए उम्मीदवार शरद तायडे (शिवसेना यूबीटी) ने सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रक्रिया की आलोचना की। महायुति को मिली भारी जीत चुनाव चक्र की शुरूआत में ही संरचनात्मक रूप से सुनिश्चित हो गई थी, जब एमवीए गठबंधन के कई उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन अपना नामांकन वापस लेने के बाद उनके छह उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए।

मुंबई लोकल ट्रेन हत्याकांड: कोच के दरवाजे को लेकर हुआ विवाद

युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

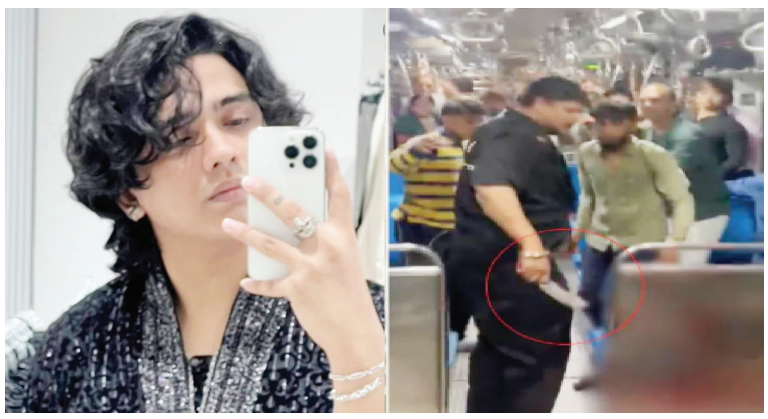

मुंबई: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मंगलवार रात को तेज बारिश के दौरान लोकल ट्रेन का दरवाजा खुला रखने या बंद करने को लेकर हुए मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि एक 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मयंक लोहार के रूप में हुई है, जो विरार के रहने वाले थे और अंधेरी के वेस्टसाइड आउटलेट में काम करते थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी रोशन सुवर्णा (30 वर्ष) को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पनवेल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मीरा-भायंदर का निवासी है और मुंबई एयरपोर्ट के कार्गो हब में बारकोड मेकर का काम करता है। पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना मंगलवार रात करीब 10:42 बजे शुरू हुई, जब मयंक और रोशन दोनों अंधेरी स्टेशन से चर्चगेट-नालासोपारा लोकल ट्रेन के फर्स्ट-क्लास डिब्बे में सवार हुए। उस समय मुंबई में भारी बारिश हो रही थी। डिब्बे का दरवाजा खुला होने के कारण बारिश का पानी अंदर आ रहा था। मयंक चाहते थे कि पानी से बचने के लिए दरवाजा बंद कर दिया जाए, जबकि रोशन दरवाजा खुला रखने की जिद पर अड़ा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

बीच-बचाव के बाद भी नहीं माना आरोपी: बोरीवली रेलवे पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर दत्तात्रेय खुपरकर ने चश्मदीदों के हवाले से बताया कि ट्रेन जैसे ही अंधेरी से बोरीवली के बीच बढ़ी, विवाद और ज्यादा उग्र हो गया। रोशन लगातार आक्रामक हो रहा था। डिब्बे में मौजूद बाकी यात्रियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और रोशन को समझाया कि खुले दरवाजे की वजह से लोग भीग रहे हैं, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। मामला शांत करने के लिए कुछ यात्रियों ने मयंक को सलाह दी कि वह डिब्बे के दूसरे दरवाजे की तरफ चले जाएं ताकि दोनों के बीच दूरी बन सके। उस समय डिब्बे में करीब 50 यात्री मौजूद थे, जिन्होंने समझाकर मामले को शांत करने की कोशिश तो की, लेकिन किसी ने भी आरोपी को शारीरिक रूप से रोकने का प्रयास नहीं किया।

अस्पताल में तोड़ा दम : घटना की सूचना मिलते ही रात करीब 11:07 बजे जीआरपी और आरपीएफ के जवान डिब्बे में पहुंचे। खून से लथपथ मयंक को तुरंत बोरीवली स्टेशन के इमरजेंसी मेडिकल रूम ले जाया गया और बाद में कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हालांकि, डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद, बुधवार तड़के इलाज के दौरान मयंक ने दम तोड़ दिया।

CCTV और पैसेंजर्स के वीडियो से पकड़ा गया कातिल : हत्यारे को पकड़ने के लिए रेलवे पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने तुरंत 7 अलग-अलग टीमें बनाईं और बोरीवली से लेकर पनवेल तक के 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले।

महाराष्ट्र एफडीए ने होटलों और रेस्टोरेंट में अखबार में खाना परोसने पर रोक लगाई

मुंबई: मुंबईकरों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए एफडीए ने मुंबई समेत राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, बेकरी, क्लाउड किचन और ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म के लिए सख्त खाद्य सुरक्षा नियम लागू कर दिए हैं। नए आदेश के तहत बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस कारोबार नहीं किया जा सकेगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक ऑडिट अनिवार्य होगा। नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य प्रतिष्ठान एफडीए की निगरानी में रहेंगे। महाराष्ट्र के नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और मिलावटमुक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए एफडीए ने व्यापक खाद्य सुरक्षा अनुपालन आदेश जारी किया है। आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा जारी आदेश के तहत वैध एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण, स्वच्छता मानकों का पालन, खाद्य पदार्थों की सुरक्षित हैंडलिंग, कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच और फूड सेफ्टी प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ ही ग्राहकों को मुफ्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना होगा। अखबार या छपे कागज में भोजन परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। उपयोग किए गए खाद्य तेल के पुनः उपयोग पर रोक लगाई गई है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने बताया की सुरक्षित भोजन हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को नए नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ना

बड़े प्रतिष्ठानों को मेन्यू में कैलोरी और एलर्जन संबंधी जानकारी देनी होगी, जबकि 50 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक एफएसएमएस ऑडिट अनिवार्य रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ना, अभियोजन, लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

इन पर लागू होगा यह आदेश

- होटल व रेस्टोरेंट
- भोजनालय व ढाबे
- कैंटीन व कैफेटेरिया
- बेकरी व मिठाई दुकानें
- कैटरिंग इकाइयां
- फूड कोर्ट व जूस बार
- क्लाउड किचन, डार्क किचन व सेंट्रल किचन चेन रेस्टोरेंट्स
- ई-कॉमर्स व ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म

Result Guarantee Above 90% or Money Back
If U R Not Joining Home Tuitions Then U R Missing Many Things
Mumbai's No.1 Premium Home Tuitions Academy
MUMBAI HOME & PRIVATE TUITIONS

1st to 10th ICSE / CBSE / IB / IGCSE / NIOS / State Boards
XI & XII Sci / Comm. IIT, NEET, MHT-CET
Engg, Degree, Diploma, B.Com, Bsc., BMS, MBA, Gmat, Cat, CET, English Speaking
Rajendra Deshmukh
MANAGING DIRECTOR
Any Class Home Tuitions Across Mumbai
Get Admission in MBBS
NEET Qualified / Unqualified Fees 25 Lacs (Inc. Food Acc.)
ADMISSIONS OPEN
Branches : Andheri - Worli - Jogeshwari - Malad - Dadar - Borivali - Virar Thane - Vashi - Nerul - Kharghar - Ambernath - Badlapur
Home Tuitions Benefits
Contact : 902 902 9222 / 80 80 80 34 12 / 8446642380 / 9209128153
https://www.mumbaihometutors.com

PRIME KEYS PROPERTIES
Beyond Dreams
BUY | SELL | RENT
FLATS · SHOPS · BUNGALOWS
LANDS · REDEVELOPMENT
Trusted Property Consultant
Residential & Commercial Deals
Best Market Price Assistance
Contact:
+91 9167378057
Your Dream Property, Our Priority

DR. ZUBER SHAH HOSPITAL & POLYCLINIC

Ambernath (W), Maharashtra
Nursing Home Reg. No.: THN-C274*
FACILITIES AVAILABLE
24x7 Emergency Care - Immediate Critical Support
Diabetology & Advanced Diabetic Care
Fever Treatment (Dengue, Chikungunya, Malaria, Influenza)
Cardiology Checkup & ECG Facility
General Medicine Consultation
Vaccination & Immunization Services
Minor Surgical Procedures
OPD & IPD Care Available
Complete Health Checkups

24 HOURS EMERGENCY SERVICE AVAILABLE
+91 9323594085 / 8237304085 | Buvapada, K B Road, Ward No. 2/2, Ambernath West, Thane, Woolen Chawl OPD : 8:00 pm to 11:30 pm | OPD Amber Care : 8149477110
DR. ZUBER S. SHAH
M.B.B.S (Reg. No. 2024020955)
Cert. in Diabetology & Emergency Medicine

एक गिलास दूध बदल सकता है आपकी सेहत

■ डॉ. आशीष मिश्रा
श्रीराम पॉलिक्लिनिक व आयुर्वेदिक दवाखाना

बा अगर आपको एक ही चीज से कई सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, तो दूध इसका सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। यही वजह है कि बचपन से ही रोज दूध पीने की सलाह की जाती रही है। एक गिलास दूध से आप शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी12, फॉस्फोरस, पोटैशियम और कई अन्य पोषक तत्व आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते बच्चों में हड्डियों और दांतों को मजबूती देने से लेकर वयस्कों में मांसपेशियों को फौलादी बनाए रखने तक के लिए दूध पीने को बहुत फायदेमंद माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि दूध सिर्फ हड्डियों और दांतों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को कई तरह से फायदे दे सकता है?

पोषक तत्वों से भरपूर है दूध

मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि दूध में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी12, राइबोफ्लेविन और कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं।

>> दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए सबसे जरूरी प्रमुख खनिज है।

>> वहीं इसमें पाया जाने वाला विटामिन डी, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है।

दूध के अन्य फायदे क्या हैं?

>> दूध में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण में मदद करता है।

>> इसमें पोटैशियम होता है, जो सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में योगदान दे सकता है।

>> दूध में विटामिन-बी12 और राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है जो ऊर्जा और तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं।

>> दूध में मौजूद फॉस्फोरस भी हड्डियों और कोशिकाओं के सामान्य कार्य में भूमिका निभाता है।

'यह परिशिष्ट किसी एक मत या संप्रदाय का प्रचार नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और सहअस्तित्व के सार्वभौमिक मूल्यों का मंच है।'

ओबरा, सोनभद्र में भगवान परशुराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न

सोनभद्रः नगर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री परशुराम के भव्य मंदिर में मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्व ब्राह्मण महासभा, वाराणसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलाकांत उपाध्याय रहे, जबकि संपूर्ण आयोजन पंडित नंदलाल पांडे के निर्देशन में विधि-विधान से संपादित हुआ। इस पावन अवसर पर शहर में महिलाओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा निकाली गई। पूजन, हवन और यज्ञ के साथ भगवान परशुराम की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की गई। तत्पश्चात विशाल भंडारे का

▸▸ श्री जनार्दन त्रिपाठी कार्यक्रम के दौरान रहे विशेष आकर्षण का केंद्र

आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान श्री जनार्दन त्रिपाठी ने अपने ओजस्वी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में दौरान शैलेंद्र चौबे, प्रमोद कुमार शुक्ला, पुष्पराज पांडे, डॉ. अरुण कुमार उपाध्याय एवं स्नेह द्विवेदी समेत कई गणमान्य वक्ताओं ने भगवान परशुराम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से श्री जनार्दन त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान परशुराम अन्याय के विरुद्ध धर्म-युद्ध के प्रतीक हैं। उन्होंने युवाओं से उनके शौर्य, तप और शास्त्र-ज्ञान को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। श्री त्रिपाठी के ओजस्वी वक्तव्य को उपस्थित जनसमूह ने करतल ध्वनि से सराहा। आयोजन समिति ने बताया कि यह मंदिर क्षेत्र में धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना का नया केंद्र बनेगा।

'आध्यात्मिक संवाद'

चातुर्मास का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में हर माह का विशेष महत्व होता है, जिसमें वर्ष के चार महीनों का खास महत्व होता है, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। सनातन धर्म में इस चातुर्मास का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरूआत होती है।

हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष चातुर्मास का शुरूआत 25 जुलाई से हो रही हो रही है जो 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर खत्म होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं, जिस दौरान सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों में विराम लग जाता है। चातुर्मास के दौरान हर तरह के शुभ कार्य और धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित होता है। इस माह में पूजा-पाठ और जाप करने का महत्व है। चातुर्मास में भगवान विष्णु चार महीने के लिए योगनिद्रा में रहते हैं जिसके कारण सभी तरह के मांगलिक कार्य थम जाते हैं। इस माह में सिर्फ भक्ति, साधना, मंत्रोचार और साधना का महत्व होता है। चातुर्मास की अवधि के दौरान साधु-संत एक ही स्थान पर रहते हुए साधना करते हैं। इस माह में पूजा और ध्यान करने से सभी तरह के फलों की प्राप्ति होती है।

चातुर्मास में क्या करें

▸▸ हर एक दिन सुबह और शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें।

▸▸ इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम, गीता और रामचरितमानस का पाठ करना शुभ रहता है।

▸▸ क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

▸▸ सात्विक और सादा भोजन करें।

चातुर्मास में क्या ना करें

▸▸ चातुर्मास में सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है।

▸▸ इन चार महीनों में विवाह, गृहप्रवेश, मुंडन, सगाई आदि करने से बचें।

▸▸ झूठ बोलने से बचें और किसी का भी अपमान करने से बचें।

▸▸ सभी तरह के धार्मिक नियमों का पालन करने से बचें।

▸▸ बेवजह की यात्रा करने से बचें।

पेज-1 का शेष

पीएम मोदी से मिले ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार...

भारत की अध्यक्षता का उद्देश्य व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाना, ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) की प्राथमिकताओं को समर्थन देना और एक सुरक्षित, मजबूत और समावेशी दुनिया बनाने में योगदान देना है।" दो दिवसीय बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। विदेश मंत्रालय (एमईए) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैठक में गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सप्लाई चेन (आपूर्ति व्यवस्था) की सुरक्षा, आतंकवादी संगठनों की ओर से इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकें, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली अस्थिरता जैसे मुद्दे शामिल थे। एमईए के अनुसार, शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने ब्रिक्स के 'आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह' और 'सूचना एवं संचार तकनीकों के सुरक्षित इस्तेमाल' से जुड़े कार्य समूहों की गतिविधियों और नतीजों की भी समीक्षा की। आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक इस साल 21-22 मई को हुई थी, जबकि सूचना और संचार तकनीक से जुड़ी बैठक इसी महीने पहले आयोजित की गई थी। बयान में कहा गया कि नेताओं ने ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का समर्थन किया। खासतौर पर सदस्य देशों की क्षमताओं को मजबूत करने, जानकारी साझा करने और आतंकवाद और साइबर खतरों से मिलकर निपटने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। उन्होंने आतंकवाद के हर रूप और हर तरीके के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीकों के इस्तेमाल को रोकने की जरूरत पर भी सहमति जताई। बैठक में शामिल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का पूरा समर्थन किया। बैठक खत्म होने के बाद सभी सुरक्षा सलाहकारों और प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

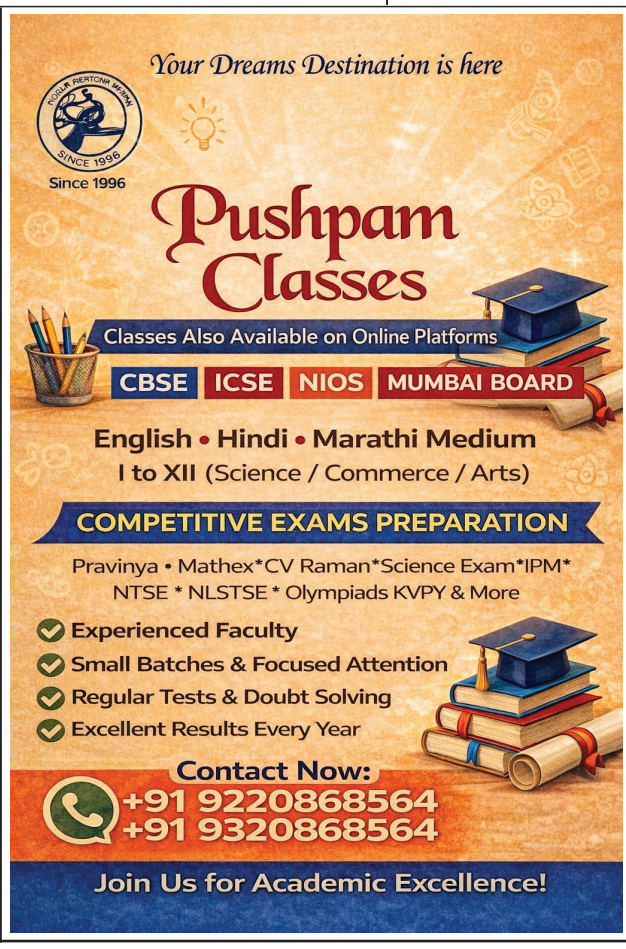

पश्चिम-एशियायाः अशान्तिः युद्धविरामस्य मध्येऽपि सङ्घर्षस्य छाया

जून-मासे २०२६ तमे वर्षे पश्चिम-एशियाक्षेत्रस्य स्थितिः दर्शयति यत् युद्धस्य तीव्रता किञ्चित् न्यूना जाता, किन्तु तस्य समाप्तिः अद्यापि न जाता। अमेरिकादेशस्य मध्यस्थतया इजरायल-लेबनान-देशयोः मध्ये वार्ताः प्रवर्तन्ते, तथापि दक्षिण-लेबनाने तनावपूर्णा स्थितिः अद्यापि वर्तते। इजरायल-देशः हिज्बुल्लाह-सङ्गटनां स्वसुरक्षायाः प्रमुखं संकटम् इति मन्यते तथा सैन्यकायार्नुष्ठानस्य अधिकारं स्वसमीपे सुरक्षितं धारयति। अपरतः लेबनान-देशः स्वकीय-भूमेः उपरि सम्पूर्ण-सार्वभौमत्वस्य सम्मानं तथा इजरायलीय-सैन्यबलस्य निष्क्रमणं प्रार्थयति। अतः युद्धविरामस्य घोषणायामपि परस्पर-अविश्वासः अद्यापि विद्यमानः अस्ति।

अन्यत्र अमेरिका-ईरान-देशयोः मध्ये पुनः संवादप्रक्रिया आरब्धा अस्ति, किन्तु आणविक-कार्यक्रमः, आर्थिक-प्रतिबन्धाः तथा क्षेत्रीय-प्रभावस्य विषयाः अद्यापि विवादस्य कारणानि सन्ति। उभौ पक्षौ प्रत्यक्ष-संघर्ष परिहरितुम् इच्छतः, तथापि परस्पर-सन्देहः पूर्णतया न निवृत्तः।

होर्मुज-जलसन्धिः अपि वैश्विक-चिन्तायाः केन्द्रं वर्तते। विश्वस्य ऊर्जा-वाणिज्यस्य महत्त्वपूर्णः भागः अस्य मार्गस्य माध्यमेन गच्छति; अतः अस्मिन् क्षेत्रे उत्पन्नः कश्चन तनावः सम्पूर्ण-विश्व-अर्थव्यवस्थां प्रभावितुं शक्नोति।

संयुक्तराष्ट्रसङ्घः तथा प्रमुख-विश्वशक्तयः संयमस्य संवादस्य च आग्रहं कुर्वन्ति। तथापि वस्तुस्थितिः एषा एव यत् पश्चिम-एशिया अद्यापि स्थायि-शान्तेः दूरम अस्ति। कूटनीतिक-प्रयत्नाः प्रवर्तन्ते, किन्तु सङ्घर्षस्य छाया अद्यापि न निवृत्ता। एषा एव अस्य क्षेत्रस्य वर्तमान-विडम्बना अस्ति।

जनसांख्यिकीय-संक्रमणस्य संधिकाले भारतम्

सैम्पल् रजिस्ट्रेशन् सिस्टम् (SRS) २०२४ इत्यस्य प्रतिवेदनानुसारं भारतस्य समग्र-प्रजनन-दरः (TFR) १.९ इति अभवत्, यदा जनसंख्यायाः स्थैर्यार्थं २.१ इति प्रतिस्थापन-स्तरः आवश्यकः मन्यते। एतत् केवलं सांख्यिकीयं परिवर्तनं न, अपितु भारतस्य जनसांख्यिक-भविष्यस्य गम्भीरः संकेतः अस्ति। देशः तादृशं चरणं प्रति अग्रे सरति यत्र वृद्धजनानां संख्या वर्धते, कार्यशील-वयस्क-वर्गस्य अनुपातश्च क्रमशः क्षीयते।

राष्ट्रीय-औसतस्य पृष्ठे स्थितं यथार्थं तु अधिकं चिन्ताजनकम् अस्ति। भारतस्य प्रायः चत्वारिंशत्-प्रतिशतं जनसमूहः तेषु राज्येषु वसति यत्र प्रजनन-दरः १.५ अथवा ततोऽपि न्यूनः अस्ति। कर्नाटके, तमिळनाडौ, केरलराज्ये च एषा प्रवृत्तिः स्पष्टतया दृश्यते। जन्मसंख्यायाः निरन्तरः ह्रासः तथा लघु-कुटुम्ब-व्यवस्थायाः प्रसारः एतस्य परिवर्तनस्य पुष्टिं करोति।

विस्मयकरं तु एतत् यत् भारतस्य बह्वयः जनसंख्या-सम्बद्धाः नीतयः अद्यापि तस्मिन् काले आधारिताः सन्ति, यदा अतिवेगा जनसंख्या-वृद्धिः प्रमुखा राष्ट्रीय-चिन्ता आसीत्। अधुना तु परिस्थितयः परिवर्तिताः सन्ति। अतः ये परिवाराः स्वेच्छया त्रयाणाम् अपत्यानां पालन-पोषणम् इच्छन्ति, ते न नीत्या न वा आर्थिक-भारैः निरुत्साहिताः भवेयुः। तथापि प्रजनन-दरस्य ह्रासस्य समाधानं केवलं जन्म-दर-वृद्धौ न निहितम्। तदर्थं मातृत्व-अनुकूल-कार्यपरिवेशः, महिलानां श्रम-क्षेत्रे व्यापकतरः सहभागः, कृत्रिम-बुद्धिमत्त्या उत्पादकता-वृद्धिः तथा आन्तरिक-श्रम-प्रव्रजनस्य प्रोत्साहनम् इत्यादयः बहुआयामिकाः उपायाः अपेक्षिताः। अधुना भारतस्य आवश्यकता जनसंख्या-नियन्त्रणस्य न, अपितु जनसंख्या-सन्तुलनस्य दृष्ट्या स्व-नीतीनां पुनर्मूल्याङ्कनस्य अस्ति। जनसांख्यिकी कस्यापि प्रतीक्षां न करोति। अतः समये एव विमर्शः, दूरदर्शी-योजना च अनिवार्या स्तः।

यदा परीक्षा निरस्ता भवति, तदा केवलं प्रश्नपत्रं न, अपितु जनविश्वासोऽपि निरस्तः भवति

अधुना भारते परीक्षासम्बद्धाः विवादाः पुनः पुनः दृश्यन्ते। प्रश्नपत्र-प्रस्रवणम्, परीक्षा-स्थगनम्, परिणामेषु सन्देहाश्च कोटिशः विद्यार्थिनां मनसि व्यवस्थायाः विश्वसनीयतां प्रति प्रश्नान् जनयन्ति। एषा समस्या केवलं तान्त्रिक-दोषस्य न, अपितु संस्थागत-सामर्थ्यस्य जनविश्वासस्य च संकटम् अस्ति।

राष्ट्रीय-परीक्षण-अभिकरणेन (ठळअ) विगतवर्षेषु विशालस्तरे परीक्षाः आयोजिताः। परीक्षार्थिनां संख्या निरन्तरं वर्धते, किन्तु तेन सह संस्थागत-सामर्थ्यस्य वृद्धिरपि अपेक्षिता। यतः कस्यापि व्यवस्थायाः सामर्थ्यं संकटसमये एव परीक्ष्यते।

अतः सुधारस्य प्रथमः आधारः सुदृढा संस्था भवेत्। परीक्षा-प्रबन्धनम्, साइबर-सुरक्षा, मनोमापन-विज्ञानम् तथा विधि-अनुपालनम् इत्यादिषु स्थायिनी विशेषज्ञता आवश्यकाऽस्ति। प्रश्नपत्र-निमार्णात वितरणपर्यन्तं सम्पूर्णा प्रक्रिया व्यक्तिनिर्भरता त्यक्त्वा प्रणाली-आधारिता भवेत्।

तन्त्रज्ञानस्य उपयोगोऽपि आवश्यकः। जैविक-परिचय-परीक्षणम्, अङ्कीय-निगराणी, दत्तांश-विश्लेषणम् तथा कृत्रिम-बुद्धिमत्ता परीक्षा-व्यवस्थां सुदृढां कर्तुं शक्नुवन्ति। किन्तु तन्त्रज्ञानं संस्थायाः विकल्पः न, अपितु तस्याः सहायकम् एव। भारतस्य विशालायां व्यवस्थायां सर्वथा दोषरहिता परीक्षा-प्रणाली कठिनाऽस्ति, किन्तु विश्वसनीया व्यवस्था अवश्यं निमार्तुं शक्यते। यतः कस्याः अपि परीक्षायाः वास्तविकं बलं प्रश्नपत्रं न, अपितु जनविश्वासः एव। तस्मात् यदा परीक्षा निरस्ता भवति, तदा केवलं प्रश्नपत्रं न, अपितु जनविश्वासोऽपि निरस्तः भवति।

विधानसभायां वादः व्यक्तिगतानाम् आरोपाणां पर्यन्तम् अगच्छत्

चेन्नईः तमिलनाडुराज्यस्य विधानसभायां मुख्यमन्त्रिणः विजयस्य विपक्षनेतुः उदयनिधि-स्टालिनस्य च मध्ये जातः राजनीतिकविवादः तदा अधिकं तीव्रः अभवत, यदा सः नीतिविषयकचर्चां त्यक्त्वा व्यक्तिगतटिप्पण्याः पर्यन्तम् अगच्छत्।

राज्यपालस्य अभिभाषणस्य उत्तरं ददन् मुख्यमन्त्री विजयः पूर्वशासनस्य भ्रष्टाचारम् आर्थिक-अनियमितताश्च विषयीकृत्य आलोचनां कृतवान्। तेन उक्तं यत् तस्य सरकारः जनधनस्य कथित-दुरुपयोगस्य विषये परीक्षणं करिष्यति। तस्य वक्तव्येन तथा संकेतात्मकाभिः टिप्पण्याभिः विपक्षः तीव्रं विरोधं प्रकटितवान्।

अनन्तरम् उदयनिधि-स्टालिनः विधानसभातः बहिः तथा 'एक्स्' इति सामाजिकमाध्यमे प्रतिक्रियां प्रदत्तवान्। सः कृषकान्दोलनस्य विषये मुख्यमन्त्रिणः उक्तीनाम् आलोचनां कृत्वा चेंगलपट्टु-नगरस्य पारिवारिकन्यायालये प्रचलितस्य विजय-संगीता-सोर्नालिङ्गम् इत्येतयोः वैवाहिकविवादस्य परोक्षरूपेण उल्लेखं कृतवान्।

उदयनिधिना आरोपितं यत् सत्तारूढदलेन विधानसभायाः गम्भीरविमर्शमञ्चः राजनीतिकप्रदर्शनस्य साधनत्वेन परिवर्तितः। अपरतः विजयस्य दलं तासां टिप्पणीनां प्रति आपत्तिं प्रकट्य उक्तवान् यत् एतादृशाः व्यक्तिगतप्रहाराः लोकतान्त्रिकमयार्दायाः विरुद्धाः सन्ति।

राजनीतिविश्लेषकाणां मते एषः प्रसङ्गः तमिलनाडोः राजनीतौ वर्धमानं ध्रुवीकरणं प्रकाशयति। अयं प्रश्नोऽपि उद्भावितः यत् लोकतान्त्रिकचर्चाः नीतिविमर्शात् दूरं गत्वा व्यक्तिगत-आरोप-प्रत्यारोपेषु परिवर्तन्ते किम् इति।

एकस्य कर्षस्य बन्धनम् (लघुनाटिका)

Dr. Vandana Mishra
M. A. NET (JRF) PHD

पात्राणि – राहुलः, अमनः, वेपः, मित्रम्,

सूत्रधारः

प्रथमं दृश्यम्

सूत्रधारः :

अद्य महाविद्यालयस्य प्रथमः दिवसः। नवीनपरिवेशे, नवीनमित्राणां प्राप्त्यर्थं च राहुलः अत्र समागतः।

राहुलः : सर्वेऽपि आत्मविश्वासेन पूर्णाः दृश्यन्ते। न जानामि, अत्र मम मित्रं कः भविष्यति।

अमनः : भोः मित्र! त्वं नूतनः छात्रः किम्? किं नाम तव?

राहुलः :

मम नाम राहुलः।

अमनः :

अस्माभिः सह तिष्ठ। एतत् एकवारं प्रयुज्य पश्य।

राहुलः :

न, न। अहम् एतस्य प्रयोगं कदापि न कृतवान्।

मित्रम् :

एकवारस्य प्रयोगेण किमपि न भविष्यति।

सूत्रधारः :

अनेकानि व्यसनानि बलात् न आगच्छन्ति; तानि मित्रतायाः आवरणेन, जिज्ञासायाः नाम्ना च जीवने प्रविशन्ति।

राहुलः :

अहो! अस्य स्वादः मधुरः अस्ति।

(वेपः शनैः प्रविशति)

वेपः (मन्दस्वरेण) :

साधु... अधुना अहं तव जीवनस्य भागः अभवम्।

द्वितीयं दृश्यम् (त्रिमासानन्तरम्)

राहुलः :

अधुना मम मनः अध्ययनस्य विषये न लगति। केवलम् एकः कर्षः लभ्येत।

वेपः :गृहाण... गृहाण त्वं शान्तिम् इच्छसि, सा मत्त एव प्राप्यते।

राहुलः : न... मया अध्ययनं कर्तव्यम्।

वेपः : केवलम् एकवारम्। ततः सर्वं सम्यक् भविष्यति।

सूत्रधारः : पूर्वं राहुलः वेपस्य नियन्त्रणं करोति स्म; अधुना तु वेपः राहुलस्य नियन्त्रणं करोति। यद् आरम्भे क्रीडावत् आसीत्, तत् शनैः बन्धनरूपं जातम्।

तृतीयं दृश्यम्

अमनः :भोः राहुल! नूतनः पॉड् आवश्यकः किम्? मूल्यं दातव्यम्।

राहुलः : मम समीपे धनं नास्ति।वेपः (उच्चस्वरेण) :

गृहात् याचस्व। मिथ्यां वद। धनं प्राप्स्यसि।

राहुलः :न! न! अलम्!

अहं क्लान्तः अस्मि। अस्य दुर्व्यसनस्य कारणात् मया स्वास्थ्यं नष्टम्, धनं नष्टम्, मातापित्रोः विश्वासश्च नष्टः। (वेपः पश्चादपसरति)

सूत्रधारः :

एषा एव व्यसनस्य वास्तविकता।

यत् प्रारम्भे सुखकरं दृश्यते, तत् अन्ते दुःखस्य कारणं भवति।

अमनः :

सः वीरः न भवति यः जनसमूहस्य अनुसरणं करोति;

वीरः तु स एव, यः अनुचितस्य सम्मुखे दृढतया 'न' इति वक्तुं शक्नोति।

सर्वे:

एकस्य कर्षस्य मूल्यं केवलं धनं नास्ति;

अपितु स्वास्थ्यं, स्वातन्त्र्यं, परिवारस्य विश्वासश्च अस्ति।

सूत्रधारः :

यदि भवान् अथवा भवतः कश्चन मित्रं निकोटीन-व्यसनस्य बन्धने पतितः अस्ति, तर्हि साहाय्यं याचत।

साहाय्यस्य याचनं न दुर्बलता, अपितु साहसस्य परिचायकः।

सर्वे (एकस्वरेण) :

एकः सम्यक निर्णयः व्यसनात् रक्षितुं शक्नोति।

एकं 'न' इति वचनं भवतः भविष्यं परिवर्तयितुं समर्थम्।

श्लोकः

सर्वेः व्यसनं नाम यो मोहः, बुद्धिनाशकरो महान्।

तस्मात् प्राज्ञो न सेवेत, स्वहिताय हितैषिणा॥

BRICS NSA meeting

Ajit Doval talks with Iran on West Asia and bilateral relations

New Delhi: National Security Advisor (NSA) Ajit Doval met Iran's Supreme National Security Council (SNSC) Deputy Secretary for Defense Ghadir Nezami on the sidelines of the 16th BRICS National Security Advisors Meeting in New Delhi on Monday. There was discussion between the two regarding the current situation in West Asia, cooperation under the BRICS platform and India-Iran mutual relations. Giving information on the social media platform 'X', Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson Randhir Jaiswal said, "NSA Ajit Doval met Ghadir Nezami, Deputy Secretary, Defense Affairs, SNSC of Iran, during the 16th BRICS NSA meeting on Monday. Both sides reviewed the current situation in West Asia. Apart from this, cooperation under BRICS and India-Iran bilateral relations were also discussed."

A two-day BRICS National Security Advisors meeting is being organized in New Delhi under the chairmanship of India. This meeting is being attended by key security officials of the member countries, who are discussing the changing security challenges in the world and considering ways to increase cooperation on strategic issues. NSA Ajit Doval also met Million Lema Tadesse, Executive Director of the Analysis Department of Ethiopia's National Intelligence and Security Service. During this, areas of cooperation were discussed to further strengthen the strategic partnership between India and Ethiopia. MEA said that in this meeting, National Security Advisors and delegation heads of BRICS countries will share their views on the topic of 'non-traditional security challenges facing the world today'.

Officials will also discuss their role in rapidly changing national security challenges and the security threats posed by new technologies. Apart from this, the results of the recently held BRICS Joint Working Group on Anti-Terrorism and Joint Working Group on Secure Use of Information and Communication Technology (ICT) meetings will also be reviewed.

Foreign Minister S Jaishankar met the President of Mongolia

Said, 'His opinion on spiritual friendship is commendable'

Ulaanbaatar: Indian External Affairs Minister S Jaishankar, who arrived in Mongolia on a two-day visit, met President Ukhna Khurelsukh in the capital Ulaanbaatar. Earlier, the Foreign Minister had also met his Mongolian counterpart B Battsetseg. Jaishankar gave details of these meetings on social media platform X. Expressing his happiness at meeting the President, he said, "It was an honor and an important meeting with President Ukhna Khurelsukh. I also conveyed warm greetings on behalf of the President of India Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi." Jaishankar further said, "President Ukhna's visit to India last year has given a new impetus to the strategic partnership between the two countries. President Ukhna's suggestion to further cooperation in various fields is commendable. I completely agree with his statement that the deepest friendship is spiritual friendship." Earlier, he also mentioned about his meeting with his Mongolian counterpart B Battsetseg. In this meeting, the progress of cooperation between the two countries in many important areas was reviewed.

After the meeting, External Affairs Minister Jaishankar said that the strategic partnership between India and Mongolia is continuously strengthening and the relations between the two countries show “affinity, strength and potential”. He said that during the discussion, development projects, capacity building, education, culture, security and cooperation on multilateral platforms were reviewed. The Foreign Minister wrote on Twitter that he was glad to visit Mongolia and looked forward to fruitful talks to further strengthen bilateral relations.

Diplomatic relations between India and Mongolia were established in 1955. India was one of the first countries to establish diplomatic relations with Mongolia and support its membership of the United Nations and the Non-Aligned Movement (NAM).After the Mongolia visit, Jaishankar will visit South Korea, where he will hold talks with his counterpart and deliver the keynote address at the Jeju Forum for Peace and Prosperity. According to the Ministry of External Affairs, after Mongolia, Jaishankar will visit South Korea on June 24 and 25, where he will hold bilateral talks with Chu-Hyun and present India's perspective on the global stage.

Development reached every sector under Yogi Adityanath's government: Jagdambika Pal

Lucknow: BJP MP Jagdambika Pal praised the tenure of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and said that under his leadership, development has now reached every village. In earlier governments, development was limited to certain places only. Speaking to IANS in Lucknow, Jagdambika Pal said, "In the SP government, development was limited only to family areas like Saifai, Mainpuri and Kannauj. In the BSP government, development work was done only in Mayawati's villages, but during the tenure of CM Yogi Adityanath, the entire Uttar Pradesh is getting overall development." He said that earlier AIIMS was being built in Saifai, but now AIIMS is being built in many places including Rae Bareli, Purvanchal. Medical colleges are being built in every district. Big projects are also going on in Basti and Ayodhya. The number of airports has also been increased. Jagdambika Pal said, "PM Modi's mantra is 'Sabka Saath, Sabka Vikas'. Yogi's double engine government is putting it on the ground. Earlier governments used to have appeasement politics, but now the benefits of all the schemes are being given not on the basis of caste-religion, but on the basis of need."

Netanyahu's big statement

IDF has complete freedom of action in southern Lebanon

Jerusalem: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israeli Defense Forces (IDF) troops deployed in southern Lebanon have complete freedom of action to prevent any direct or emerging threat against them or against residents of northern Israel. He said that the instructions given by him and the Defense Minister to the IDF are very clear and no changes have been made to them. Netanyahu said, "Our troops in southern Lebanon have complete freedom to stop any direct or potential threat against themselves or against the residents of the north. There are no restrictions on the IDF in this matter. I stand with them and the entire country stands with them." He added, "I maintain our position that we will remain in the security zone in southern Lebanon for as long as necessary to protect the residents of the north and all Israeli citizens."Earlier in the day, US Vice President JD Vance informed the media about the progress of ongoing talks between the US and Iran in Switzerland.On the issue of Lebanon, Vance said "very good progress" has been made in talks. He said that a 'de-confliction mechanism' is being prepared whose aim is to prevent the confrontation between Israel and Hezbollah from turning into a major regional conflict. He said that I believe that we have been quite successful in establishing what we are calling 'de-conflict mechanism'.

India is giving unique and unmatched economic opportunities to the world: Piyush Goyal

New Delhi: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that today India is providing unique and unmatched economic opportunities to the world. He said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is establishing itself as a reliable global economic partner. Addressing the 'Republic Summit 2026', Goyal said India's growing role in global supply chains and trade policies that prioritize national interest have made India an attractive destination for businesses across the world. "India is set to play an increasingly important role in global supply chains as companies around the world look for trustworthy and reliable partners," he said. Goyal said companies from across the world are increasingly attracted to India due to the strong economic base, stable policy environment and growth-oriented reforms implemented by the Modi government. He said India's economic progress has created unprecedented opportunities for investors, traders, exporters and industries. The Union Minister said that all the trade agreements made by India in recent years have been done keeping in mind the national interests. These agreements have also strengthened trade relations between India and its global partners. He said that these agreements are aimed at creating more opportunities for Indian traders, exporters, industries and citizens, while also ensuring complete protection of India's interests. Referring to the government's approach in international trade negotiations, Goyal said that the government led by Prime Minister Modi has always adopted the policy of 'Nation First'. He said that every trade agreement has been designed in such a way that it increases economic development and employment opportunities in the country. Goyal said, "Modi government is fully committed to protecting the interests of farmers." He also reiterated the government's commitment to protect the interests of farmers and said agricultural concerns remain a major consideration in India's trade policies and negotiations. The Union Minister said that India is gradually emerging as a major hub of the global supply chain. Also, India is likely to benefit greatly from the diversification of manufacturing and sourcing activities across the world. He said that India will play a more important role in the field of global trade and investment in the coming years.

PUPILS TIMES

Friday, 26 June to 2 July 2026

Padma awards to 65 celebrities

President honored Rohit Sharma with Padma Shri and Alka Yagnik with Padma Bhushan

New Delhi: President Draupadi Murmu on Tuesday honored 65 celebrities, including tennis legend Vijay Amritraj, cricketer Rohit Sharma, actors Satish Shah and Mammootty and playback singer Alka Yagnik, with the prestigious Padma awards.The President honored these personalities in a function organized at the Republic Pavilion of Rashtrapati Bhavan. He honored former Supreme Court Justice KT Thomas for public service and Malayalam journalist P Narayanan with Padma Vibhushan for his contribution to literature and education. Alka Yagnik, Mammootty, American oncologist Dattatreyudu Nori, Vijay Amritraj, industrialist SKM Mailainandan and social activist and educationist Vellappally Natesan received the Padma Bhushan award from the President. While the Padma Bhushan award of late Jharkhand Mukti Morcha (JMM) founder Shibu Soren was received by his wife Rupi Soren. Rupi Soren had arrived in a wheelchair. The President came down from the stage and presented him the award. President Murmu honored Rohit Sharma and hockey player Savita Punia with Padma Shri. Under the captaincy of Rohit, India won the 2024 T20 World Cup title. Georgian coach Vladimir Mestvirishvili, who mentored Indian Olympic medalists like Sushil Kumar, Yogeshwar Dutt and Ravi Dahiya, was posthumously honored with the Padma Shri award. His wife received this honour. The President honored actor Satish Shah with Padma Shri posthumously. His brother accepted this honor on his behalf. Former Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati was also awarded the Padma Shri. He is currently the Chairman of CBFC. Among the Padma Shri awardees are actor R Madhavan, Defense Research and Development Laboratory aerospace scientist Chandramouli Gaddmannu, who played a key role in the deployment of the Akash missile system during Operation Sindoor, and Dalit writer Ashok Kumar Haldar were awarded the Padma Shri. The President presented 65 Padma awards at the ceremony, including two Padma Vibhushan, seven Padma Bhushan and 56 Padma Shri.

After BrahMos, India's new roar in the world defense market!

New Delhi: The story of India's defense exports, till now, was mainly revolving around the 'BrahMos' supersonic missile, but now this story is about to take a new and historic twist. The United Arab Emirates (UAE), one of the most advanced armies in the world, has shown keen interest in India's indigenous air defense system named 'Akashtir'. This news is not only a victory for Indian engineering, but also a proof of 'self-reliant India' becoming a major power in the defense sector. The United Arab Emirates (UAE) has shown interest in purchasing the BrahMos missile as well as the Akashtir air defense system. This development can prove to be very important for India's defense industry. In fact, the threat of these two Indian weapons has increased in the world defense market because if BrahMos is a symbol of India's offensive power, then Akashteer is going to be the face of its defensive technology export.

Big message behind UAE's interest : UAE's move towards 'Akashteer' is a matter of great pride for India. UAE already uses the world's most expensive air defense systems like America's 'THAAD' and 'Patriot'. In such a situation, choosing India's defense technology proves that the Indian defense system is not only economical but in quality is at par or better than the best options in the world.

Army Chief and Indian Ambassador to China stressed on strengthening relations with Beijing

New Delhi: Indian Ambassador to China Vikram Doraiswami met Indian Army Chief General Upendra Dwivedi. During this, both of them discussed the changing regional and global strategic environment. Also discussed were measures to further strengthen the existing framework of bilateral cooperation and dialogue between India and China. The Indian Army issued a statement on 'X' saying, "India's Ambassador to China Vikram K. Doraiswamy met Army Chief General Upendra Dwivedi. The main topic of discussion was the changing regional and global strategic scenario. They reviewed the current status of bilateral relations and discussed ways to further strengthen the existing mechanism of cooperation and interaction." It is noteworthy that on Monday, National Security Advisor Ajit Doval had met Chinese Foreign Minister Wang Yi during the two-day BRICS meeting at the NSA level in New Delhi. During the discussions, both sides reviewed recent developments in bilateral relations and noted the gradual progress towards normalization.

Lucknow fire: Yogi government in action mode

Statewide campaign will be run against illegal coaching centers

Lucknow: Lucknow. After the tragic fire at the coaching center in Lucknow, Uttar Pradesh, the Yogi government has decided to launch a big campaign regarding the safety and validity of the coaching institutes running across the state. The government has instructed all the district magistrates to identify illegal coaching centers and take action against them and also to conduct special audit of fire safety, building and electrical systems of registered institutions. Higher Education Minister Yogendra Upadhyay has clearly said that the safety of students and the quality of education will not be compromised at any level. The Uttar Pradesh government has decided to launch a comprehensive investigation and verification campaign against the coaching centers operating across the state. On the instructions of Chief Minister Yogi Adityanath, strict action will be taken against illegally operating coaching institutes by identifying them, while a special audit of the security arrangements of the registered institutes will also be conducted. He said that as per the intention of Chief Minister Yogi Adityanath, a safe, systematic and reliable educational environment is being created for the youth preparing for competitive examinations. The government's priority is to provide quality education to every student along with a safe learning environment.

In this regard, a letter has been issued to all the District Magistrates by Special Secretary Higher Education Fund Srivastava. In the letter, along with identifying the institutions operating without registration and ensuring action under the provisions of the Act, the safety of students in registered coaching institutions,

Congress is going to start 'Students' Echo' campaign

Responsibility assigned to 28 leaders

Congress has announced to organize press conferences across the country under the 'Students' Echo' campaign. For this campaign, All India Congress Committee (AICC) has assigned responsibilities to 28 leaders in different cities. The party says that this initiative is being started to demand comprehensive reforms in the education system of the country. Congress has started this campaign with the demand for the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. The party alleges that the education policy of the present government lacks vision and has failed to address the challenges of the education sector. The statement issued by the Congress said that in the last 12 years, the BJP and RSS led government has promoted privatization, centralization and federalization of education. The party claims that the government has not taken adequate steps to prepare the youth for future needs. According to Congress, today the country is facing not only unemployment but also a serious problem like lack of employable skills. The party says that without improving the education system, it will not be possible to ensure better opportunities for the youth. Congress said that the 'Students' Echo' campaign will not be limited to just press conferences, but it is the beginning of a national dialogue.

LIC

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

"With you in life, and after life"

POPULAR LIC PLANS:

- Jeevan Labh — Limited Premium, High Returns
- New Children's Money Back — Secure Your Child's Future
- Jeevan Umang — Whole Life Cover + Pension Benefits
- Bima Jyoti — Guaranteed Additions, Safe Growth
- Also Available – Complete Financial Planning Guidance

KEY BENEFITS:

- Life Insurance + Savings Plan
- Child Education and Marriage Planning
- Retirement Planning
- Tax Benefits Available

भारतीय जीवन बीमा निगम

"जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी"

FREE POLICY CONSULTATION

LIC Agent

Archana Shukla

+91 91129 39085

+91 74998 67628

Shop No. 2, Near Vithal Mandir, New Vadavali Chowk, Badlapur (West) – 421503

LIC Agent ID: 04497939

PUPILS TIMES

Core Committee

Anurag Shukla
Chief Editor

Shivprakash Pandey
Chief Publisher

Vikas Maurya
Co Publisher

Address: Shop No. 3, Khatri NX Aprt., Valivali, Badlapur (West) - 421503

Contact: 9004331751

Web: pupilstimes.com

(The editor does not necessarily agree with the news, articles, and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai courts.)

ANURAG SHUKLA CHIEF EDITOR . Mob.: +91 9167378057, E-mail: anurag@pupilstimes.com. www.pupilstimes.com

Printes, Published & Owned by : **ANIL MISRA,** Printed at **SOMANI PRINTING PRESS,** UNIT NO. 04, GROUND FLOOR, N. K. INDUSTRIAL ESTATE, OFF. AAREY ROAD, GOREGAON (E.), MUMBAI, MAHARASHTRA - 400064. **Published at :** 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA). (The editor does not necessarily agree with the news, artical and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai court) Editor - **ANIL MISRA** , Mob. : 92208 68564, **Email :** anilmisrapc@gmail.com. **PRGI. No. : MHMUL/25/A2419**